(b) NCCF have recovered the full amount of loss from the eirip-ployees concerned on whom minor penalities were also imposed.

दालों की उपलब्धता

1934. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार अजमेर सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दालों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दालों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पिछले तीन दशकों के दौरान दालों के उत्पादन और आयात में लगातार वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दशकों के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरन्तर कमी आई है ;

(घ) यदि हां, तो 60, 70 और 80 के दशकों के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या रही है ; और

(ङ) भविष्य में 90 के दशक में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां। देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए) चूंकि देश में पैदावार देश में मांग के अनुरूप नहीं हुई है; इसलिए देश में दालों की आपूर्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से खुले सामान्य लाइसेंस पर दालों का आयात करने की अनुमति दी गई है और दालों पर आयात शुल्क भी 35 प्रतिशत से घटाकर पहली नवम्बर, 1989 से 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित नीतियां अपनाई गई हैं :—

(1) दुगुनी और बहु फ़सली जैसी सिंचित खेती प्रणाली में दालों की फ़सलें लगाना शुरू करना।

(2) निम्नलिखित के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र लाना :—

(क) गर्मी में सरसों, गन्ने, आलू और गेहूं की फ़सल के बाद सिंचाई सुविधाओं के साथ दालों की और रबी मौसम में मसूर की खेती करना।

(ख) उत्तरी राज्यों में गेहूं के साथ रोटेशन में अल्पावधि के लिए अरहर की खेती करना।

(ग) रबी मौसम में अवशेष नमी का इस्तेमाल कर चावल से खाली हुई भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि की किस्मों की खेती करना।

(3) सिंचित और असिंचित दोनों स्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ने और मूंगफली में अरहर की अन्तराल फ़सल की पैदावार करना।

(4) उन्नत बीजों, पौध संरक्षण उपाय करना, फ़ास्फ़ैटिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना और रिजोबियम संवर्धन जैसे आदानों का अधिक प्रयोग करना।

उपर्युक्त नीति को निम्नलिखित दो कार्यक्रमों से भी बल मिलता है :—

(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम।

राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 से चलाया जा रहा है।

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अधीन सेंट्रल सेक्टर कार्यक्रम :

(क) पाड बोरर, कट वार्म और दीमक से चने और अरहर की सुरक्षा करने के लिए पौध संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना ।

(ख) ग्रीष्म मूंग उड़द के अधीन क्षेत्र में विस्तार करना ।

(ख) 1960-61 से 1989-90 तक के वर्षों में दालों के स्वदेशी उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए है :--

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन में)
1960-61	12.70
1970-71	11.82
1980-81	10.63
1983-84	12.89
1984-85	11.96
1985-86	13.36
1986-87	11.71
1987-88	10.96
1988-89	13.76
1989-90 (प्रत्याशित)	14.00--14.50

पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :--

वर्ष	आयात की गई मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1	2
1983-84	2.28
1984-85	2.35
1985-86	4.30
1986-87	6.25
1987-88	5.87
1988-89	8.27
1989-90 (दिसम्बर, 1989 तक	2.51 (अनन्तिम)

(ग) से (ङ) पिछले कुछ दशकों में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता नीचे दी गई है :--

वर्ष	प्रतिदिन उपलब्धता ग्राम में
1951	60.7
1960	65.5
1970	51.9
1980	30.9
1989	40.4

(अ०)--अनन्तिम

(ऊपर दिए गए आंकड़े देश में खपत की वास्तविक मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं विशेषतया इस वजह से कि इनमें व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के पास पड़े स्टाक में किसी परिवर्तन को हिसाब में नहीं लिया गया है।)

8वीं योजना में दालों की जरूरत के लक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

Allotment of flats to slum dwellers

1935 SHRI SYED SIBTEY RAZI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Slum Wing ofDDA had invited applications in 1985 for allotment of residential flats from slum dwellers;